

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2983
जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....
बांधों का निर्माण

2983. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित किए गए नए बांधों के निर्माण प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) इस संबंध में लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

- (क) पिछले 4 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान नए बांधों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं, जैसाकि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, के ब्यौरे को अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
- (ख) वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन नए बांधों हेतु सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावों की स्थिति को अनुलग्नक-11 (1 एवं 2) में दिया गया है।

“बांधों का निर्माण” विषय पर लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 2983 के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले चार वर्षों तथा वत्तेमान वर्ष में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा बांध निमोण सहित स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र.	समिति की बैठक	बैठक की तिथि	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना का प्रकार
1	128वीं	29.02.2016	जिगांव सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	नए, बृहद
2	129वीं	08.07.2016	सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना	गुजरात	तीसरी आरसीई, बृहद
3	129वीं	08.07.2016	दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना	महाराष्ट्र	नए, पेयजल
4	129वीं	08.07.2016	केन बेतवा लिंक परियोजना (चरण-I)	उत्तर प्रदेश	नए, बृहद
5	129वीं	08.07.2016	भौरनरात बांध परियोजना	उत्तर प्रदेश	नए, मध्यम
6	130वीं	30.09.2016	बुढ़ही जलाशय परियोजना	झारखंड	बृहद, नए
7	130वीं	30.09.2016	पवई सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	नए, मध्यम
8	132वीं	06.03.2017	रेणुकाजी बांध परियोजना	हिमाचल प्रदेश	बहुउद्देशीय
9	132वीं	06.03.2017	उत्तरी कोइल जलाशय परियोजना	बिहार और झारखंड	बृहद, आरसीई
10	135वीं	12.03.2018	परवान बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना	राजस्थान	नए, बृहद, सिंचाई
11	136वीं	06.06.2018	ऊपरी प्रवरा (निलवांडे-II) परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	महाराष्ट्र	आरसीई, बृहद सिंचाई
12	137वीं	28.08.2018	जिगांव सिंचाई परियोजना का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)	महाराष्ट्र	आरसीई, बृहद सिंचाई
13	138वीं	31.10.2018	शाहपुर कंडी बांध परियोजना की संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)	पंजाब	आरसीई, बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना
14	135वीं	12.03.2018	कनहर बैराज परियोजना	झारखंड	बृहद, नई सिंचाई
15	136वीं	06.06.2018	ऊपरी प्रवरा (निलवांडे-II) परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	महाराष्ट्र	आरसीई, बृहद सिंचाई
16	137वीं	28.08.2018	जिगांव सिंचाई परियोजना का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)	महाराष्ट्र	आरसीई, बृहद सिंचाई
17	138वीं	31.10.2018	शाहपुर कंडी बांध परियोजना का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)	पंजाब	आरसीई, बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना
18	139वीं	07.01.2019	उझ बहुउद्देशीय परियोजना	जम्मू एवं कश्मीर	बृहद, बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना
19	141वीं	11.02.2019	लखवर बहुउद्देशीय परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	उत्तराखंड	बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना
20	141वीं	11.02.2019	जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	उत्तराखंड	बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई
21	141वीं	11.02.2019	पोलावरम सिंचाई परियोजना का संशोधित लागत अनुमान	आंध्र प्रदेश	बृहद सिंचाई, राष्ट्रीय परियोजना

* - लवादोनी बांध का इस परियोजना के अंतर्गत निमोण किया जाना प्रस्तावित है।

“बांधों का निर्माण” विषय पर लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 2983 () में उल्लिखित अनुलग्नक

मूल्यांकनाधीन परियोजनाओं की सूची, जिसमें नए बांधों का निर्माण शामिल है।

क्र.	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना का प्रकार	परियोजना की वर्तमान स्थिति
1	पार-तापी नर्मदा लि परियोजना	गुजरात	बृहद	संबंधित राज्य सरकार ने अंतराज्यीय तथा सिंचाई परियोजना आयामों के संबंध में अपनी सहमति नहीं दी है।
2	बीना कॉम्प्लेक्स सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजना	मध्य प्रदेश	बृहद	हाइड्रोलॉजी सहित अंतराज्यीय आदि विभिन्न आयामों को स्वीकार कर लिया गया है। राज्य सरकार ने अंतराज्यीय स्वीकृति, सीएमसी, सिंचाई आयोजना आदि सहित अन्य पहलुओं के संबंध में अपनी सहमति नहीं दी है।
3	पूर्वोत्तर राजस्थान नहर परियोजना	राजस्थान	बृहद	अंतराज्यीय, सीएमडीडी तथा हाइड्रोलॉजी आयामों को स्वीकार कर लिया गया है। राज्य सरकार ने पहलुओं जैसे हाइड्रोलॉजी, सिंचाई आयोजना, संयंत्र आयोजना, डिजाइन आदि के संबंध में अपनी सहमति नहीं दी है।
4	कालीसिंध बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना चरण-II।	राजस्थान	बृहद	अंतराज्यीय, सीएमडीडी पहलुओं को स्वीकार कर लिया गया। राज्य सरकार ने पहलुओं जैसे हाइड्रोलॉजी, सिंचाई आयोजना, संयंत्र आयोजना, डिजाइन आदि के संबंध में अपनी सहमति नहीं दी है।
5	जंवाई बांध को भरने के लिए साबरमती बेसिन के अतिरिक्त जल डायवर्जन	राजस्थान	*	राज्य सरकार द्वारा हाइड्रोलॉजी तथा अंतराज्यीय आयामों को सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया है।
6	यमुना के जल के राजस्थान हिस्से ताजेवाला हेडवर्क्स से दू. में अंतरण हेतु डीपीआ तथा राजस्थान के झुंझुन जिले में भूमिगत कवेस प्रणाली तथा उसका उपयोग	राजस्थान	बृहद	सीडब्ल्यूसी ने सिंचाई आयोजना, संयंत्र आयोजना, लागत, अंतराज्यीय मामलों, बीसीडी के संबंध में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है।
7	ऊपरी सिकासर जलाशय परियोजना (पीएफआर)	छत्तीसगढ़	बृहद	हाइड्रोलॉजी, अंतराज्यीय मामलों तथा सिंचाई आयोजना पहलुओं को सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत कर दिया गया।
8	खारूंग-अहिरन परियोजना (पीएफआर)	छत्तीसगढ़	बृहद	हाइड्रोलॉजी, अंतराज्यीय मामलों तथा सिंचाई आयोजना पहलुओं को सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत कर दिया गया।
9	डंडपानी टैंक परियोजना (पीएफआर)	छत्तीसगढ़	बृहद	हाइड्रोलॉजी, अंतराज्यीय मामलों तथा सिंचाई आयोजना पहलुओं को सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत कर दिया गया।

10	शेखरपुर बृहद परियोजना (पीएफआर)	छत्तीसगढ़	बृहद	हाइड्रोलॉजी, अंतर्राज्यीय मामलों तथा सिंचाई आयोजना पहलुओं को सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत कर दिया गया।
11	मेकेदातू बैलेंसिंग जलाशय सह पेयजल परियोजना	कर्नाटक	बहुउद्देशीय	डीपीआर को सीडब्ल्यूएमए के सामने रखा गया।
12	इंद्रापुरी जलाशय परियोजना (पीएफआर)	बिहार	बृहद	हाइड्रोलॉजी, अंतर्राज्यीय, सिंचाई आयोजना पहलुओं को <u>सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत कर दिया गया।</u>
13	निचली वंशधारा परियोजना (चरण-1)	ओड़िशा	बृहद	मामले को वीडब्ल्यूडीटी के न्यायाधीन रखा गया है। ओड़िशा ने मई, 2018 में सशोधित डीपीआर प्रस्तुत की।
14	सांग बांध पेयजल परियोजना	उत्तराखंड	*	राज्य सरकार द्वारा हाइड्रोलॉजी तथा डिजाइन आयामों को <u>सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया।</u>
15	टेल एकीकृत बहुउद्देशी परियोजना	ओड़िशा	बृहद	इसमें अंतर्राज्यीय आयाम हैं। महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया।
16	मध्य कोलाब बहुउद्देशी परियोजना	ओड़िशा	बहुउद्देशीय	पहलू जैसे हाइड्रोलॉजी, सिंचाई, लागत, डिजाइन, सीईए, एफई एवं एसए, इंस्ट्रुमेंटेशन आदि के संबंध में टिप्पणियों को राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
17	तेलीजोरे परियोजना-पीएफआर	ओड़िशा	बृहद	इसमें अंतर्राज्यीय आयाम हैं। महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया।

* पूर्ण रूप से पेयजल परियोजना।

“बांधों का निर्माण” विषय पर लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2983 () में उल्लिखित अनुलग्नक

परियोजना प्रस्तावों (राष्ट्रीय परियोजनाएं) की सूची, जिसमें नए बांधों का निर्माण शामिल हैं, जोकि वर्तमान में सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकनाधीन है।

क्र . .	राष्ट्रीय परियोजना/राज्य का	स्वीकृतियों का ब्यौरा
1	रेणुकाजी बांध परियोजना/हिमाचल प्रदेश	परियोजना की लागत को सीडब्ल्यूसी द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया है। परियोजना प्राधिकरण ने बीसी रेसियो कम्प्यूटेशंस के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।
2	केन-बेतवा लिंक परियोजना/मध्य एवं उत्तर प्रदेश	एनडब्ल्यूडीए द्वारा मसौदा व्यापक डीपीआर प्रस्तुत की गई है।
3	कुलसी बांध परियोजना/असम	परियोजना के स्वामित्व तथा वित्त पोषण का निर्णय असम सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।
4	नोआ दिहिंग बांध परियोजना/अरुणाचल प्रदेश	राज्य ने अपने पक्ष के वित्त पोषण का निर्णय नहीं लिया है।
5	बुरसर जल विद्युत परियोजना/जम्मू एवं कश्मीर	परियोजना प्राधिकरण ने कमान क्षेत्र के ब्यौरे प्रदान नहीं किए हैं।
6	किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना/हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड	परियोजना प्राधिकरण के द्वारा संशोधित डीपीआर प्रस्तुत नहीं की गई है।